

This question paper contains 8+3 printed pages]

HPAS (M)—2014

PUBLIC ADMINISTRATION

Paper II

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 150

Note :— Attempt five questions in all. Question No. 1 is compulsory. All questions carry equal marks.

कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्र. 1 अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. Answer the following in about 100 words :

- (a) How did Kautilya conceptualize the notion of 'an absolutist state' in his treatise, *Arthashastra* ?
- (b) Critically elaborate the 1882 Ripon resolution.
- (c) How do you say that India is a federal country despite the fact that according to Article-1 of the Constitution of India 'India that is Bharat shall be a union of states' ? Elaborate your answer.

P.T.O.

- (d) Trace critically the evolution of public enterprises in India in the light of the famous Avadi resolution in 1955
- (e) How do you account for the excessive importance of the Prime Minister's Office in India ? Elaborate your response.

निम्नलिखित का 100 शब्दों में उत्तर दीजिए :

- (a) कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में किस प्रकार 'एक पूर्ण राज्य' की अवधारणा को संकल्पित किया है ?
- (b) 1882 के रिपन प्रस्ताव का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए।
- (c) इस तथ्य के बावजूद कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद-1 में कहा गया है कि 'इंडिया जो भारत है राज्यों का एक संघ है,' आप किस प्रकार कह सकते हैं कि भारत एक संघीय देश है ? विस्तार से उत्तर दीजिए।

- (d) 1955 के विख्यात आवाडी प्रस्ताव के संदर्भ में लोक निगमों के विकास को आलोचनात्मक रूप से चिन्हित कीजिए।
- (e) भारत में प्रधान मंत्री कार्यालय के बढ़ते महत्त्व को आप किस प्रकार वर्णित करते हैं ? विस्तारपूर्वक उत्तर दीजिये।

2. Answer the following in about 200 words :

- (a) Do you think that Article-311 of the Constitution of India is a morally appropriate provision in the context of growing democratization in India ?
Elaborate your answer.
- (b) Structurally, Indian administration is hardly a break with the past. Do you agree with this view ?
Elaborate your response.

निम्नलिखित का 200 शब्दों में उत्तर दीजिये :

- (a) भारत में बढ़ते लोकतंत्रीकरण के संदर्भ में क्या आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद-311 को नैतिक रूप से उचित प्रावधान मानते हैं ? विस्तारपूर्वक उत्तर दीजिए।
- (b) संरचनात्मक रूप में भारतीय प्रशासन अपने भूतकालीन रूप से शायद ही भिन्न है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं ? अपने उत्तर को विस्तारपूर्वक लिखिये।

3. Answer the following in about 200 words :

- (a) Identify and briefly elaborate *five* major recommendations of the 2005 Second Administrative Reforms Commission.
- (b) How do you defend that the Seventy-Third Amendment Act of 1992 is a breakthrough in so far as gender-equality is concerned ? Elaborate your response.

निम्नलिखित का 200 शब्दों में उत्तर दीजिये :

- (a) 2005 के दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के पाँच मुख्य सुझावों को चिन्हित कर संक्षेप में व्याख्यान कीजिए।
- (b) आप किस प्रकार इस बात का समर्थन करते हैं कि तेहत्तरवें संशोधन अधिनियम, 1992 महिला-समानता के संदर्भ में एक नवीनता लिए हुए है ? विस्तारपूर्वक उत्तर दीजिए।

4. Answer the following in about 200 words :

- (a) Critically evaluate the role of the National Human Rights Commission of India in discharging its role as a protector of human rights in India.
- (b) In what circumstances, the President of India can be an authority with substantial power in accordance with the Constitution of India ? Elaborate your response.

P.T.O.

निम्नलिखित का 200 शब्दों में उत्तर दीजिये :

(a) भारत में मानव अधिकार संरक्षक की भूमिका के तौर पर भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए।

(b) भारतीय संविधान के अनुरूप, किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति एक संपूर्ण सत्ता शक्ति का रूप ग्रहण करता है ? अपने उत्तर को विस्तार से लिखिये।

5. Answer the following in about 200 words :

(a) The 2005 Right to Information Act is an offshoot of a sustained struggle at the grass roots. Do you agree with this view ? Elaborate your answer.

- (b) What formula did the erstwhile Planning Commission of India apply to allocate funds to the constituent states ? Elaborate your answer with reference to the major functions of the former Planning Commission of India.

निम्नलिखित का 200 शब्दों में उत्तर दीजिये :

- (a) 2005 का सूचना अधिकार कानून सत्ता के निम्नतम स्तर पर हुए संघर्षों का फल है। क्या आप इस बात से सहमत हैं ? अपने उत्तर को विस्तार से लिखिये।
- (b) भारत का पूर्ववर्ती योजना आयोग राज्यों को किस आधार पर धनराशि का आबंटन करता था ? भारत के पूर्ववर्ती योजना आयोग के मुख्य कार्यों के संदर्भ में अपने उत्तर को विस्तारपूर्वक लिखिये।

6. Answer the following in about 200 words :

(a) What are the major arguments that are being pursued for withdrawal of protection for public sector units since the Seventh Five Year Plan (1985-1990) ? Elaborate your response.

(b) Critically evaluate the role of the District Planning Committee as a means to democratize planning at the grass roots.

निम्नलिखित का 200 शब्दों में उत्तर दीजिये :

(a) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-1990) से लोक निगमों के संरक्षण वापसी के लिए मुख्य क्या तर्क दिए गये हैं ? अपने उत्तर को विस्तारपूर्वक लिखिये।

- (b) शासन के निम्नतम स्तर पर लोकतांत्रिक योजना के माध्यम के रूप में जिला योजना कमेटी की भूमिका की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।

7. Answer the following in about 200 words :

- (a) Despite being integral to the administrative cadre, the state Chief Secretary acts as a mouthpiece of the political leadership in power. Do you agree with this view ? Elaborate your response with reference to the principal functions that the Chief Secretary is expected to discharge.

- (b) Critically evaluate the role of Public Accounts Committee as a constitutional authority.

निम्नलिखित का 200 शब्दों में उत्तर दीजिये :

- (a) प्रशासनिक केडर के आंतरिक अंग होने के बावजूद राज्य मुख्य सचिव सत्तारूढ़ राजनीतिक नेतृत्व के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं ? मुख्य सचिव के प्रमुख कार्यों के संदर्भ में अपने उत्तर की विवेचना कीजिए।
- (b) एक संवैधानिक निकाय के तौर पर लोक लेखा कमेटी के कार्य की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।

8. Answer the following questions in about 200 words :

- (a) A minister brings values to administration while a secretary of a ministry articulates those values in devising appropriate policies. Explain.
- (b) Critically evaluate the role of the Comptroller and Auditor General of India as a constitutional watchdog of public expenditures.

निम्नलिखित का 200 शब्दों में उत्तर दीजिये :

(a) एक मंत्री प्रशासन में मूल्यों को निरूपित करता है, जबकि एक सचिव उन मूल्यों को उचित नीतियों में निरूपित करता है। चर्चा कीजिए।

(b) लोक व्यय के एक संवैधानिक प्रहरी के रूप में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की भूमिका का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए।